(b) No, Sir.

(c) Steps are being taken by the Government to increase the inflow of tourists to India by improving the tourism infrastructure and strengthening the marketing efforts.

Report on Airbus crash at Bangalore

93. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Bhatt Commission appointed to probe into crash of Indian Airlines Airbus A-320 at Bangalore has submitted its report;

(b) if so, what are the details of its findings; and

(c) what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) to (c) The report of the Court of Inquiry, along with the Government's decisions thereon, has been tabled in the House on 10th January, 1991. The Court of Inquiry had made 62 recommendations. Action has been initiated to implement the recommendations accepted by the Government.

Fleet requirements of airlines

94. SHRI MAHENDRA PRASAD:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have lately reviewed the aircraft fleet requirements of Indian Airlines, Air India and Vayudoot;

(b) if so, what is the outcome thereof; and

(c) what steps are contemplated by Government to augment and update the fleet for meeting the requirements of these Corporations indicating the nature and number of aircraft to be procured or deinducted?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) to (c) The fleet requirements of Air India and Indian Airlines are kept under constant review. Both Air India and Indian Airlines have been directed recently to prepare a long term perspective plan for fleet renewal so that the fleet is kept young and modern. With due consideration to commercial viability, availability of financial resources, and other relevant factors, the fleet of both the national carriers would be renewed from time to time.

As regards Vayudoot, given the facts that it has accumulated losses, the options concerning its future are under the consideration of the Government.

कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र में हानि

95. श्री राम नरेश यादव :
श्री अरंगिल श्रीधरन् :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर की सैर करने वाले पर्यटकों से हुई आय का ब्यौरा क्या है तथा पर्यटन के क्षेत्र में हानि के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत के कारण वहां पर्यटन उद्योग में गिरावट आई है ;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में आ रही रूकावटों को दूर करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर और विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले औसत खर्च पैटर्न के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में पर्यटन से होने वाली प्राक्कलित आय इस प्रकार रही—

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आय	% अन्तर
1988	100.98	—
1989	87.00	−13.8
1990	3.10	−96.4

(ख) जी, हां । घाटी की वर्तमान परिस्थिति ने वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है ।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर के राज्य के अन्य भागों में पर्यटन से संबंधित आधारिक-संरचना में सुधार ला कर और अधिक पर्यटकों को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

कूड़े करकट से विद्युत का उत्पादन

96. **श्री राम नरेश यादव** : क्या विद्युत और गैर- पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या निगमों के कूड़ा-करकट तथा धान की भूसी से विद्युत तैयार करने की योजना सफल हुई है ; यदि हां, तो क्या सरकार इसका और विस्तार करने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार अब तक कितना व्यय कर चुकी है तथा अगले वर्ष के दौरान उस पर कितना व्यय करने का विचार है ; और

(ख) भारत में बिजली की मांग तथा आपूर्ति में कितना अन्तर है तथा सरकार अगले पांच वर्षों में इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) शहरी अपशिष्टों के निपटान और विद्युत उत्पादन के लिए धान पुआल जैसे अतिरिक्त कृषि अवशिष्टों के इस्तेमाल हेतु अनुसंधान और विकास शाखाओं के साथ कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं । ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अभी सिद्ध होनी है तथा उसके बाद ही आगे परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा ऐसी परियोजनाओं के संबंध में अब तक कुल लगभग 46 करोड़ रुपये व्यय किया गया है जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपये की कुल विदेशी उदार ऋण सहायता और कुल लगभग 6 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है ऐसी योजनाओं पर चालू वर्ष के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है ।

(ख) अप्रैल से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान 68815 मिलियन यूनिट ऊर्जा की अखिल भारतीय आवश्यकता की तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता 62772 मिलियन यूनिट थी जिससे 8.8% की कमी आई है ।

विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में नई उत्पादन क्षमता को प्रारंभ करने में शीघ्रता करना, लघु परिपक्वता अवधि की परियोजनाओं का कार्यान्वयन, वर्तमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, संचरण और वितरण से होने वाली हानियों में कमी लाना, मांग प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना और बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा सप्लाई करना शामिल है ।

उत्तर प्रदेश में एल० पी० जी० (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) बाटलिंग प्लाट

97. **श्री राम नरेश यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने एल.पी.जी. (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) बाटलिंग प्लांट हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं तथा क्या सरकार आजमगढ़ जिले की